Power stations in Punjab

1051. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of power-station proposed for installation in Punjab during the Eighth Plan togetherwith the details thereof;

(b) how many of them have been commissioned so far; and

(c) by when 66 K. V. Babarpur Power Grid, Patiala, prpposed in the year 1991-92 is likely to be installed/ commissioned alongwith the progress made, if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) The 8th Five Year Plan envisaged that the following projects would yield benefits in Punjab during the plan period:

Sl. No.	Name of the Project/Capacity in MW	Type of Project	Benefits during 1992—97 (in MW)
1	Thien Dam (4×150)	Hydro	300
2	Ropar-III (210)	Thermal	210
3	Bhatinda* (420)	Thermal	420

* Proposed for Private Sector participation.

None of these projects has been commissioned so far.

(c) Information is being obtained from Government of Punjab.

विष्णु प्रयाग बहु उद्देशीय परियोजना

1052. **श्री अजीत जोगी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विष्णु प्रयाग बहु-उद्देशीय परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि का पूर्ण उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए इस प्रयोजनार्थ केवल 100 करोड़ रुपए की सिफारिश किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी है ;

(घ) इस कार्य को पूरा करने में अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) विष्णु-प्रयाग जल विद्युत परियोजना (4×65.5 मे. वा.) को जुलाई 1978 में स्वीकृति दी गई थी । 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत आवंटित राशि की तुलना में 1985-1990 के दौरान 5.6 करोड़ रु. का खर्च हुआ ।

(ख) निधियों की कमी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा परियोजना को कम प्राथमिकता दी जा सकी और 1991-92 की वार्षिक योजना में एक करोड़ रुपए की सांकेतिक निधि का प्रावधान किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजनाओं 1992-93 एवं 1993-94 में परियोजनाओं के लिए किसी परिव्यय का प्रावधान नहीं किया था ।